06.09.2023

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

बीमा मंथन
Bima Manthan

भारतीय बीमा उद्योग के साथ संवाद
-Interaction with the Indian Insurance Industry

बीमामंथन – बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ एक आवधिक बैठक 4 और 5 सितंबर 2023 को हैदराबाद में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) में आयोजित की गई। यह फोरम बीमा उद्योग के साथ निरंतर परस्पर क्रिया और संवाद के लिए एक आधार के रूप में काम आता है। इस संबंध में गहन विचार-विमर्श, चर्चाएँ और अंतर्दृष्टि, *`2047 तक सबके लिए बीमा'* का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ भारत में बीमा की वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में सामूहिक समर्पण को रेखांकित करती हैं।

इस लक्ष्य की दिशा में *बीमामंथन* के चौथे संस्करण ने बीमा क्षेत्र में प्रचलित वृद्धि के अवसरों तथा इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए कार्यनीतियों का उद्देश्य रखनेवाली सुदृढ़ चर्चाओं और प्रस्तुतीकरणों का साक्षात्कार किया। इस बैठक ने विषयों के एक दायरे में गहन विचार-विमर्श को प्रमुख स्थान दिया, जो बीमा क्षेत्र में उभरते जोखिमों से लेकर नवोन्मेष उत्पाद विकास, संरक्षण के अंतरालों को पाटने, वितरण दृष्टिकोण का नवीकरण करने, तथा बीमा तक पहुँच का विस्तार करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाने तक व्याप्त है। सहभागियों ने गंभीरतापूर्वक चर्चाएँ कीं और अंतिम गम्यस्थान तक पहुँचने के लिए व्यावहारिक समाधान पहचानने के लक्ष्य से युक्त विचारोत्तेजक प्रस्तुतीकरण किये।

इसके अलावा, बीमा उद्योग के द्वारा की गई प्रगति और राज्य बीमा योजना (एसआईपी) को गति देने के लिए कार्यनीतियों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। एसआईपी अंतिम लक्ष्य तक पहुँचने में एक प्रमुख समर्थक है जिसमें पूरे राज्य भर में बीमा तक पहुँच का विस्तार करने के उद्देश्य के साथ राज्य /संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित किये गये हैं।

जोखिम आधारित पूँजीगत ढाँचा (आरबीसी), जोखिम आधारित पर्यवेक्षण ढाँचा (आरबीएसएफ) तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) के कार्यान्वयन में की गई प्रगति पर भी चर्चा की गई। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि आरबीसी के अंतर्गत प्रथम मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस-1) प्रारंभ किया जा चुका है तथा आरबीएसएफ के अंतर्गत प्रथम प्रायोगिक अभ्यास भी प्रारंभ किया गया है। उक्त मानक की अधिसूचना के बाद कार्यान्वित किये जानेवाले आईएफआरएस के अंगीकरण के लिए दी गई रूपरेखा के अनुसार अनुसरण की जानेवाली पद्धति की संक्षिप्त जानकारी भी बीमाकर्ताओं को दी गई। भविष्य के लिए तैयार, सिद्धांत आधारित संरचना में संक्रमण के लिए उद्योग द्वारा सुदृढ़ उत्साह और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई।

बीमा की उपलब्धता, पहुँच और वहनीयता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। इस संदर्भ में गतिशील आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के उत्पादों को समझने के लिए तथा बीमा कंपनियों की भौगोलिक उपस्थिति बढ़ाने के महत्व एवं पहुँच में वृद्धि करने के लिए वितरण कार्यनीतियों में बढ़ोतरी करने, एवं इस प्रकार *सबके लिए बीमा* के मिशन की दिशा में अग्रसर होने के संबंध में भी विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क (एमएफआईएन) और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के पास पंजीकृत स-धन, स्व-विनियामक संस्थाओं के सीईओएस ने भी वित्तीय समावेशन, सूक्ष्म बीमा संबंधी परिप्रेक्ष्य प्रस्तावित करते हुए बीमा उद्योग के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श किया। उन्होंने उन सहक्रियाओं पर भी फोकस किया जिनकी साझेदारी एमएफआईएस, एनबीएफसी, एसएफबीएस, आदि तथा बीमा उद्योग के व्यापक नेटवर्क के बीच की जा सकती है। उन्होंने अपने द्वारा आपूर्ति किये जानेवाले बाजार तथा उन पद्धतियों पर भी प्रकाश डाला जिन्हें बीमाकर्ता देश में बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए काम में ला सकते हैं।

उक्त बैठक ने उद्योग के मानकों का उन्नयन करने, नवोन्मेषण का संवर्धन करने, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि जोखिम न्यूनीकरण और वित्तीय सुरक्षा के लिए बीमा एक अनिवार्य साधन बना रहेगा, बीमा और पुनर्बीमा क्षेत्र की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

Bima Manthan - a periodic meeting with the CEOs of Insurance and Reinsurance Companies was held at the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) Headquarters on 4th and 5th September, 2023 at Hyderabad. This forum serves as a cornerstone for continuous interaction and dialogue with the insurance industry. The deep discussions, deliberations and insights underscore the collective dedication towards propelling growth and development of insurance in India with an aim to achieve '*Insurance for All by 2047*'.

Towards this end, the fourth edition of *Bima Manthan* witnessed robust discussions and presentations aimed at growth opportunities prevailing in the insurance sector and the strategies to tap such opportunities. The meeting featured intense deliberations on a spectrum of topics, ranging from emerging risks in the insurance sector to innovative product development, strategies to bridge the protection gaps, revamping distribution approach and enhancement of role of technology in expanding the access of insurance. The participants engaged in profound discussions and showcased thought-provoking presentations aimed at identifying pragmatic solutions to reach the last mile.

Further, progress made by insurance industry and strategies to accelerate State Insurance Plan (SIP) were also discussed in detail. SIP is a major enabler in reaching the last mile wherein states/UTs have been assigned to insurers with an objective of expanding access to insurance across the length and breadth of the state.

The progress made towards implementation of Risk Based Capital Framework (RBC), Risk Based Supervision Framework (RBSF) and International Financial Reporting Standards (IFRS) was also discussed. It was highlighted that first Quantitative Impact Study (QIS-1) under RBC has already been rolled out and first pilot exercise under RBSF has also been commenced. The glide path outlined for adoption of IFRS to be implemented after notification of the standard was also

briefed to the insurers. Strong enthusiasm and commitment was displayed by the industry for transitioning into a future ready, principle based architecture.

Emphasis was also placed on ensuring Availability, Accessibility and Affordability of insurance. In this context, detailed deliberations were carried out to understand the various types of products needed to cater the dynamic requirements and importance of increasing the geographical presence of insurance companies & enhancing the distribution strategies to increase accessibility, thus moving towards the mission of *Insurance for All.*

The CEOs of Micro Finance Institutions Network (MFIN) and Sa-Dhan, the Self-Regulatory Organizations registered with Reserve Bank of India (RBI) also interacted with the insurance industry offering perspective on financial inclusion, micro insurance and focused on synergies that can be shared between the wide network of MFIs, NBFC, SFBs, etc. and insurance industry. They also threw light upon the market they cater to and the ways in which insurers can harness it to increase insurance penetration in the country.

The meeting reaffirmed the collective commitment of the insurance and reinsurance sector to advancing the industry's standards, promoting innovation, and ensuring that insurance remains a vital tool for risk mitigation and financial security.

***